2 अध्याय

भारतीय अर्थव्यवस्थाः समस्याएं एवं समाधान

इस अध्याय में आप सीखेंगे कि:

- भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की परम्परागत व वर्तमान समस्याएँ।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के सरकारी प्रयास।
- सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन।

परिचय (Introduction)

आज यदि भारत मज़बूती के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिये अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, परमाणु अप्रसार संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons—NPT) पर हस्ताक्षर न करने के बाद भी उसे परमाणु शस्त्र आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Supplier Group—NSG) की सदस्यता के मुद्दे पर चीन सहित एक-दो देशों को छोड़कर शेष सभी राष्ट्रों का समर्थन मिल रहा है। विश्व की शीर्ष संस्थाओं आईएमएफ व विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की शीर्ष गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था घोषित किया है और विश्व के सबसे ताकतवर देश की 'कांग्रेस' हमारे प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान बार-बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती हो, हाल ही में जापान के साथ भारत का असैन्य परमाणु करार ने वैश्विक जगत में भारत की स्थिति और मजबूत की है। ये सब कही-न-कही वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत होती आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy)

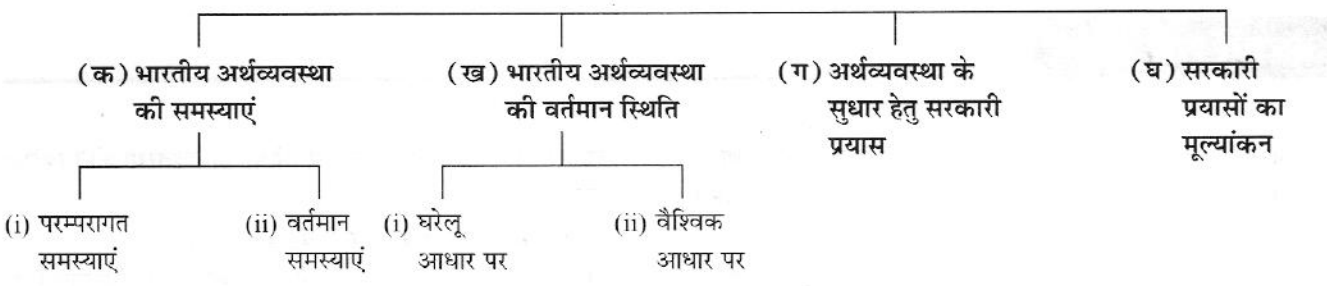

भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं (Challenges to Indian Economy)

भारत सदैव से ही सम्पूर्ण विश्व के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहाँ कई विदेशी शासक आए, जिनमें से कुछ लूट-पाट करने के उद्देश्य से आए तो कुछ भारत में ही बस गये और यहीं के होकर रह गये, परन्तु सन् 1757 में हुए प्लासी के युद्ध ने भारत के भाग्य बदल दिये क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत पर ब्रिटिश (अंग्रेज़ों) का औपनिवेशिक शासन शुरू हो गया, जो 200 वर्षों तक चला। परिणामत: भारतीय अर्थव्यवस्था जिसके वैभव के चलते उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था एक पंगु अर्थव्यवस्था के रूप में

स्वतंत्रता के पश्चात् प्राप्त हुई। तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने उस समय की भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में कहा था कि 'भारत आधुनिक औद्योगिक पूंजीवाद का एक सक्रिय एजेंट बन गया है, जो अपनी सभी बुराईयों से पीड़ित है तथा जिसका कोई भी अपना लाभ नहीं है।' भारतीय अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है— 1. परम्परागत समस्याएं
2. वर्तमान समस्याएं

1. **परम्परागत समस्याएं**—भारतीय अर्थव्यवस्था की परम्परागत समस्याएं 200 वर्षों के औपनिवेशिक काल की देन है, जो निम्नवत् हैं—
   - निम्न प्रतिव्यक्ति आय
   - पूँजी का अभाव
   - कृषि की प्रधानता एवं कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव
   - परिसम्पत्तियों का दोषपूर्ण वितरण
   - निम्न स्तर की तकनीक
   - औसत भारतीयों का निम्न जीवन स्तर
   - औद्योगिक क्षेत्रों का अल्प विकास या पिछड़ापन
   - असन्तुलित आर्थिक विकास
   - आर्थिक कुचक्रों की प्रबलता
   - आधारभूत संरचनाओं—बिजली, सड़क व परिवहन का अल्पविकास
2. **वर्तमान समस्याएं**—भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष परम्परागत समस्यायें, जिन्हें पिछले 6 दशकों से नियंत्रित करने का प्रयास जारी है, परन्तु आशातीत सफलता हाथ नहीं लगी। आर्थिक सुधारों (1991) के बाद कई नवीनतम् समस्याएं भी उत्पन्न हुईं, जो निम्नवत् हैं—
   - खाद्य मुद्रास्फीति की दरों में वृद्धि।
   - जीडीपी वृद्धि दर की धीमी गति।
   - बैंकों की बढ़ती गैर-निष्पादित सम्पत्तियां।
   - रोजगार के नये अवसर सृजित करने की धीमी दर।
   - कोर क्षेत्र से संबंधित उद्योगों की वृद्धि दर का निम्न बने रहना।
   - अप्रत्यक्ष करो की जटिलता के चलते एफडीआई के प्रवाह की धीमी गति।
   - भारतीय अर्थव्यवस्था को एकल बाजार के रूप में विकसित न कर पाना।
   - व्यापार शेष की स्थिति का नकारात्मक बने रहना।
   - भारत को 'वैश्विक बाजार' के रूप में बनी अपनी छवि को न तोड़ पाना।
   - भारतीय मुद्रा रूपये का डालर के सापेक्ष कमज़ोर होना।
   - बढ़ता राजस्व व राजकोषीय घाटा।
   - विदेशी मुद्रा भण्डार का सशक्त न होना।
   - अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का निम्न योगदान।
   - भारत में 'उद्यमशीलता की संकल्पना' का अभाव।
   - वित्तीय समावेशन की कमज़ोर स्थिति।
   - युवाओं में कौशल विकास का अभाव।
   - वैश्विक अर्थव्यवस्था की उथल-पुथल से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना।
   - लघु व कुटीर उद्योग के विकास हेतु वित्त प्रबन्धन में देरी।
   - कृषि उत्पादन व उत्पादकता का निम्न स्तर।
   - जोखिम पूंजी (Venture Capital) का अभाव।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति (Current Status of Indian Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन घरेलू व वैश्विक आर्थिक संकेतको के माध्यम से किया जा सकता है—

तालिका 2.1: भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन

आर्थिक संकेतक (घरेलू)	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जीडीपी वृद्धि दर	% में	7.2	8.0	7.1 (अं.अ.)	6.5 (प्र.अं.)
बचत दर	जीडीपी के % के रूप में	33.1	32.3	NA	NA
पूँजी निर्माण दर	जीडीपी के % के रूप में	34.4	33.3	NA	NA
राजस्व घाटा	जीडीपी के % के रूप में	2.9	2.5	2.1	1.9 (बजट अनुमान)
राजकोषीय घाटा	जीडीपी के % के रूप में	4.1	3.9	3.5	3.2 (बजट अनुमान)
प्राथमिक घाटा	जीडीपी के % के रूप में	0.9	0.7	0.4	0.1 (बजट अनुमान)
प्रतिव्यक्ति आय	वर्तमान मूल्य पर	86,454	94,130	1,03,219	1,11,782
मुद्रास्फीति दर	थोक मूल्य सूचकांक पर	1.2	-3.7	1.7	2.9*

(Continued)

तालिका 2.1: भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन *(Continued)*

आर्थिक संकेतक (घरेलू)	इकाई	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
मुद्रास्फीति दर	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर	5.9	4.9	4.5	3.3*
विदेशी मुद्रा कोष	बिलियन अमेरिकी डॉलर में	341.6	360.2	370.0	409.4*
विदेशी ऋण	अरब डॉलर में	475.7	485.0	471.8 (R)	493.7 (P)*
कुल खाद्यान्न उत्पादन	मिलियन टन में	252.02	251.6	275.7	134.7#
कृषि ऋण	लाख करोड़ में	8.0	8.5	9.0 (बजट अनुमान)	10.0 (बजट अनुमान)
एफडीआई(FDI) का अंतप्रर्वाह	बिलियन अमेरिकी डॉलर में	31.3	55.56	60.08	33.75●

अं.अ = अनन्तिम अनुमान, प्र.अं. = प्रथम अनन्तिम आकड़े, * अप्रैल–दिसम्बर 2017 R = आरक्षित (रिजर्वड) P = अस्थायी (प्रोविजनल) # केवल खरीफ फसल शामिल है। ● = अप्रैल–सितम्बर 2017 की स्थिति

तालिका 2.2: भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का वैश्विक स्तर पर मूल्यांकन

आर्थिक संकेतक (वैश्विक)	जारीकर्ता	कुल देश	भारत का रैंक	चीन का रैंक
सतत विकास इंडेक्स 2017	सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट सॉल्यूशन नेटवर्क (12 जुलाई, 2017 को जारी)	157	116	71
विश्व मानव पूँजी सूचकांक 2017	विश्व आर्थिक मंच द्वारा (13 सितम्बर 2017 को जारी)	130	105	–
वैश्विक शांति सूचकांक 2017	इंस्टीट्यूट फार इकोनामिक्स एंड पीस (21 जून, 2017 को जारी)	163	137	116
वैश्विक भूख सूचकांक 2017	इंटरनेटलेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (12 अक्टूबर, 2017 को जारी)	119	100	29
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018	विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (31 अक्टूबर, 2017 को जारी)	190	100	78
वर्ल्ड हैप्पीनैस इंडेक्स 2017	यूनाइटेड नेशन्स सस्टेनेबल डवलपमेंन्ट सोलूशन्स नेटवर्क द्वारा कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अर्थ इंस्टीट्यूट के सहयोग से (20 मार्च, 2017 को जारी)	155	122	79
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2017	रिपोर्टस विदाउट बोर्डर्स (26 अप्रैल, 2017 को जारी)	180	136	176
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017	द हेरिटेज फाउंडेशन एवं वाल स्ट्रीट जर्नल (5 फरवरी, 2017 को जारी)	186	143	144
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक 2017 (International Intellactual Property Index)	वैश्विक बौद्धिक संपदा केन्द्र (8 फरवरी, 2017 को जारी)	45	43	22
वैश्विक लैगिंक अंतराल सूचकांक 2017	विश्व आर्थिक मंच (29 नवम्बर 2017 को जारी)	144	108	100

उपरोक्त घरेलू व वैश्विक संकेतक भारतीय अर्थव्यवस्था की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे है, जिसमें अभी कई रंग भरने शेष है। यदि हम घरेलू आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन करें तो कुछ सकारात्मक तथ्य जैसे जीडीपी वृद्धि दर में पहले की तुलना में सुधार देखने को मिला है इसी क्रम में हमारे प्रमुख घाटे राजस्व, राजकोषीय व प्राथमिक घाटों की स्थिति में सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रतिव्यक्ति आय में सकारात्मक वृद्धि हुई है, खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति भी पहले से बेहतर है और एफडीआई, के अंत: प्रवाह में वृद्धि सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत व अहम निर्णय लेने का ही परिणाम है जिसके कारण इस क्षेत्र में भी भारत की स्थिति मजबूत हो रही है, विदेशी निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश के लिये आकर्षित हुए हैं, परन्तु इन सकारात्मक पहलुओं के सापेक्ष कुछ नकरात्मक तथ्य भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त है, जैसे—बचत व पूँजी निर्माण की दर में कमी तथा

बढ़ता विदेशी ऋण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ स्थिति में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है।

विदेशी संकेतकों को आधार बनाकर यदि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन किया जाये तो यह अवश्य ज्ञात हो जायेगा कि भारत सभी अच्छे सूचकांकों जैसे—सतत विकास सूचकांक, मानव पूँजी सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक व वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में सौ शीर्ष देशों में अपना स्थान नहीं बना सका।

अर्थव्यवस्था के सुधार हेतु सरकारी प्रयास (Government Efforts to Improve Economy)

भारतीय अर्थव्यवस्था में परम्परागत व वर्तमान समस्याओं के बावजूद भी विकास की अपार संभावनाएं मौजूद है और सरकार उक्त सभी समस्याओं (परम्परागत व वर्तमान) के समाधान की दिशा में चरणबद्ध तरीके से बढ़ती दिख रही है जहाँ एक तरफ नए निवेश लाने के लिए बीमा, पेंशन, फार्मास्यूटिकल्स, ई-कामर्स एवं रक्षा क्षेत्र में एफ.डी.आई. से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार किये गए हैं, वही दिवालियापन कानून (Bankruptcy Law) के आने के बाद जिन फर्मों की खराब वित्तीय स्थिति होगी, उनके निर्गमन का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा। सरकार राष्ट्रीय अवसंरचना एवं निवेश कोष (NIIF) के गठन से लेकर लघु व सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुद्रा (MUDRA) योजना लेकर आई है। वहीं कौशल भारत अभियान भी युवाओं को स्वावलंबी बनाने में प्रभावी साबित होगा। इसके अलावा सरकार युवाओं को नौकरी खोजने वाले के स्थान पर नौकरी देने वाले के रूप में परिणत करने के लिए 'स्टार्ट अप इंडिया' जैसी मुहिम चला रही है, जो युवा उद्यमियों के लिये स्वर्णिम अवसर के मार्ग खोलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा 7 सूत्रीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है, जिसमें बैंकों के शासन से लेकर पुन: पूंजीकरण (Recapitalization) तक के कदम शामिल हैं। जीएसटी, अप्रत्यक्ष करो में देश का अब तक का सबसे बड़ा सुधार है जिससे देश भर में समान कर व्यवस्था स्थापित होगी। सामाजिक क्षेत्र में भी शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर कार्य चल रहा है तथा लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे कार्यक्रम चला रही है, साथ ही 'समेकित बाल विकास सेवा' के तंत्रों को भी सशक्त एवं प्रभावी बनाने हेतु प्रयास हो रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में सुधार हेतु महिला सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण शर्त है उज्जवला योजना को इस क्षेत्र में ठोस कदम के रूप में देखा जा सकता है।

कृषि की महत्ता को समझते हुए सरकार ने बजट 2018-19 में कृषि क्षेत्र को 11 लाख करोड़ रूपये के ऋण का आवंटन किया है। मनरेगा को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए कृषि कार्यों के साथ इसके समन्वय के प्रयास किये जा रहे है। जरूर ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तथा यूरिया के दुरूपयोग को रोकने के लिये नीम यूरिया का उत्पादन जैसे कदम सकारात्मक परिणाम देंगे।

सरकारी प्रयासों का मूल्यांकन

नवगठित सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास हेतु—श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण शहरी मिशन (रूर्बन मिशन), स्वच्छ भारत अभियान, नमामि-गंगे, सागर माला योजना, भारतमाला योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण पहल की। आर्थिक क्षेत्र के विकास हेतु-स्वर्ण मुद्राकरण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सार्वभौमिक स्वर्ण बॉन्ड योजना का प्रारम्भ किया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में—सुकन्या समृद्धि योजना, उज्जवला योजना महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आयुष्मान योजना (बजट 2018-19 में घोषित) का प्रारम्भ किया। उपरोक्त योजनाओं का परिणाम यह रहा कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था आईएमएफ द्वारा 22 जनवरी, 2018 की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की सर्वोच्च वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया है। आईएमएफ व विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये अनुमानित व पुर्वानुमानित वृद्धि दर के आंकड़े व विश्व एवं ब्रिक्स देशो में तुलनात्मक अध्ययन को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है

तालिका 2.3: वैश्विक संगठनों द्वारा सम्पूर्ण विश्व, भारत व ब्रिक्स देशों की वृद्धि दर के अनुमानित व पूर्वानुमानित आंकड़े (% में)

जारीकर्ता	विश्व बैंक			आइएमएफ			
(i) रिपोर्ट का नाम	ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट			वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट			
(ii) प्रस्तुत	10 जनवरी 2018 में जारी की गयी			22 जनवरी 2018 में जारी की गयी			
(iii) प्रदर्शन	2017 (अनुमान)	2018 (लक्ष्य)	2019 (लक्ष्य)	2017 (अनुमान)	2018*	2019*	2020*
• सम्पूर्ण विश्व	**3.7**	**3.9**	**3.9**	**3.0**	**3.1**	**3.0**	**2.9**
• भारत	6.7	7.4	7.8	6.7	7.3	7.5	7.5
• चीन	6.8	6.6	6.4	6.8	6.4	6.3	6.2
• रूस	1.8	1.7	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8
• ब्राजील	1.1	1.9	2.1	1.0	2.0	2.3	2.5
• द.अफ्रीका	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	1.7	1.7

* पूर्वानुमान

अध्याय सार संग्रह

- प्लासी के युद्ध के पश्चात् भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन प्रारम्भ हुआ।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख परम्परागत समस्याएँ है—निम्न प्रतिव्यक्ति आय, पूँजी का अभाव, औद्योगिक क्षेत्रों का अल्प विकास या पिछड़ापन तथा आधारभूत संरचना का सीमित विकास।
- भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख वर्तमान समस्याएँ है—बैंकों का बढ़ता एनपीए (NPA) खाद्य मुद्रास्फीति, बचत व पूँजी निर्माण की धीमी दर, नकारात्मक व्यापार शेष और वित्तीय समावेशन की धीमी प्रक्रिया।
- भारत सरकार की आर्थिक विकास की योजनाएं हैं—मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सहज योजना, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्टार्ट अप इंडिया, सेतु भारतम् योजना, स्टैंड अप इंडिया व प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- भारत सरकार की सामाजिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएं हैं—मातृत्व लाभ, कार्यक्रम, प्रधानमंत्री, उज्जवला योजना, किलकारी योजना, इन्द्रधनुष योजना, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं योजना व सुकन्या समृद्धि योजना।